

कर्ज से बन रही परियोजनाएं निपटाना चुनौती

अंतरराष्ट्रीय बैंकों की होती कड़ी शर्तें

एशियन डेवलपमेंट बैंक के अलावा अन्य अंतरराष्ट्रीय बैंकों से लोन हासिल करने पर उनकी कड़ी शर्तों का पालन भी करना होता है। लोन की अवधि से ज्यादा का समय परियोजना में लगता है तो बैंक और लोन से मना कर देते हैं। इस रियासत में द्वांचागत विकास के अलावा शहरी विकास निवेश कार्यक्रम को लोन हासिल करने की तरफ ध्यान केंद्रित किए है। अभी केवल एडीबी से ही लोन मिला है। अब विश्व बैंक, जापान इंटरनेशनल बैंक और अन्य अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से भी संपर्क करने का लक्ष्य है।

जम्मू-कश्मीर में निर्माण कार्य करवाने वाली सरकारी संस्था इकोनामिक रिकंस्ट्रक्शन एजेंसी (इरा) के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी) के सहयोग से जम्मू-कश्मीर में निर्माणाधीन परियोजनाओं को 31 दिसंबर 2016 तक पूरा करवाना बड़ी चुनौती है। एशियन डेवलपमेंट बैंक के लोन की समय सीमा 31 दिसंबर को समाप्त हो जाएगी। ऐसे में जिन परियोजनाओं के लिए लोन मिला है वे इस तिथि तक पूरा नहीं होती हैं तो उनके लिए और पैसा नहीं मिलेगा। ऐसे में अधूरी परियोजनाओं को पूरा कराने के लिए राज्य सरकार को पैसा देना होगा। जम्मू-कश्मीर इरा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) विनोद शर्मा से विभिन्न पहलुओं पर संजीव दुबे की बातचीत के मुख्य अंश...



विनोद शर्मा सीईओ, इरा

चिनाब पेयजल प्रोजेक्ट को अभी नहीं मिला लोन

जम्मू के लिए अहम चिनाब पेयजल परियोजना के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने लोन को मंजूरी प्रदान नहीं की। इस वजह से अब अन्य अंतरराष्ट्रीय बैंकों खासतौर से जापान इंटरनेशनल बैंक से संपर्क किया जा रहा है। चिनाब पेयजल परियोजना की जम्मू शहर के लिए काफी अहमियत है। इसके लिए सरकार जैसा चाहेगी, इरा कोशिश करेगी कि परियोजना जल्द शुरू हो। परियोजना काफी बड़ी है, इसलिए राशि का इंतजाम बेहद जरूरी है।

संकर्री गलियों में आती है मुश्किल

पुराने शहरों की संकर्री गलियों में निर्माण कार्य करने, खासतौर से चार-पांच फुट की गली में ड्रेनेज या सीवररेज या पानी के पाइप डालने के कार्य में कई परेशानियों से जूझना पड़ता है। विभिन्न विभागों से संपर्क साधने, रास्ता बद होने और परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण करने के मामलों में समय बर्बाद होता है। परियोजनाओं में देरी होने की आशंका बनी रहती है।



1600 करोड़ की राशि से बनाई कई परियोजनाएं

जम्मू और श्रीनगर में फ्लाई ओवर के निर्माण के अलावा 613 किलोमीटर तक सड़क निर्माण, 25 पुलों का निर्माण, जम्मू पश्चिम में सीवररेज प्रोजेक्ट, 424 किलोमीटर तक पीएचई के पुराने पाइपों को हटाकर नए पाइप डालने का कार्य, 39 किलोमीटर तक ड्रेनेज कार्य, 10 ओवर हेड टैंक और 19 ट्यूबवेल का निर्माण, चार पीएचई पंपिंग स्टेशनों, 36 सुलभ शौचालयों के अलावा जम्मू और श्रीनगर में मल्टी स्टोरी पार्किंग आदि का निर्माण किया जा चुका है या कार्य करवाया जा रहा है।

JICA to provide technical assistance for J&K projects

NEW DELHI, Feb 11:

The Japan International Cooperation Agency (JICA) today said it will provide technical assistance to Government for development of national highways in mountainous regions like Jammu & Kashmir, Uttarakhand and Himachal Pradesh.

"JICA has signed a technical cooperation agreement with the Government for 'capacity development project on highways in mountainous regions', it said in a statement.

The project will provide for strengthening of institutional capacity of organisations engaged in development of road network in mountain terrains, such as Ministry of Road Transport & Highways (MoRTH), NHA, NHIDCL and state-level PWDs.

The road ministry has assigned high priority to the development of national highways in the mountainous regions to enhance local connectivity, especially in Uttarakhand, Himachal Pradesh, Jammu &

Kashmir and the North-East region.

"MoRTH is keen to adopt new technologies related to tunnels, bridges and slope stabilisation and enhance its capacities for disaster-resistant planning, cost-effective construction technologies and safety management in mountainous highways," the statement said.

Under the JICA's cooperation, technical guidelines will be prepared for design, development and management of road network in mountainous regions, including for tunnels, high-pier bridges, earthworks, slope protection and waterways for the drainage.

JICA will dispatch experts from Japan on highway engineering and management, and conduct technical training programmes for Indian engineers and technical personnel, in partnership with the Indian Academy of Highway Engineers, to enhance capacity of Government in planning, construction and management of highways in mountainous regions.

The Agency has been continuously cooperating with MoRTH and other road agencies in their human resource development and improvement and construction of highways since early 1990s when JICA started dispatch of Japanese experts to those organisations, it said.

The newly-started technical cooperation represents JICA's attempts to further its cooperation in the transport sector, which would play a pivotal role for economic and social development in India. (PTI)